P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-1* April - 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

माध्यमिक शिक्षा और समस्याएँ

वैशाली चौधरी
शोध छात्रा,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
मोनाड़ यूनिवर्सिटी,
हापुड़

सारांश

''भारत में शिक्षा कोई नवीन बात नहीं हैं सासंर का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रेम की परम्परा भारत से अधिक प्राचीन व शक्तिशाली है।''

शिक्षा प्राप्त करने का उददे्श्य केवल जीविकोपार्जन करना ही नही । या वरन् शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का एक साधान माना गया था। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होतो है। ज्ञान से ही उसके मस्तिष्क का विकास होता है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है उस आध्यातित्मक और पारलौकिक विषयों की अनुभूति होने लगती है तभी ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है। ज्ञान अथवा विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह सद्रमार्ग का रास्ता दिखाती हैं।

मुख्य शब्द : प्राचीन, शक्तिशाली, जीविकोपार्जन, मस्तिष्क, आध्यात्मिक, परलौकिक, अनुभूति।

प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसे माध्यमिक शिक्षा कहते है। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. निम्न माध्यमिक स्तर (Lower Secondary Stage)
2. उच्च माध्यमिक स्तर (Higher Secondary Stage)

यह शिक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा शिक्षा जगत की सबसे कमजोर कड़ी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस स्तर पर विश्व में सबसे अधिक लोग इसी शिक्षा को प्राप्त करते हैं ओर इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद या तो किसी व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकि शिक्षा में प्रवेश पाते है, या उच्च शिक्षा में प्रवेश पाते है।, या शिक्षा को छोड़ देते है और किसी अन्य कार्य में लग जाते है। कमजोर कड़ी इसलिए कही जाती है। क्योकि यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है, जिसमें कई कमियाँ है।

इसके सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा जगत की सबसे कमजोर कड़ी है। यह परिणाम में अत्यधिक है, तथा गुणात्मक स्तर पर दोषपूर्ण है। (माध्यमिक शिक्षा आयोग)

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (Secondary Education Act) 1960 ने भी माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है – वह **''शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।''**

माध्यमिक शिक्षा व्यक्ति की किशोरावस्था के साथ सम्बन्धित है। इस स्तर पर बच्चे के शारीरिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक हें माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् और विश्वविद्यालय की शिक्षा के आरम्भ होने तक के समूचे शिक्षा काल को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती हैं।

प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले कई अध्यापक केवल माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पाते है, जन पर प्राथमिक शिक्षा के स्तर के बनाने का उत्तरदायित्व है इसलिए इसके गुणात्मक विकास पर ध्याान दिया जाना चाहिए। राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं तकनीकि कुशलताओं पर भी माध्यमिक शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। यह नवयुवको, सामाजिक निर्माण तथा राष्ट्र की आर्थिक उन्नत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है।

शिक्षा का उददे्श्य

अब शिक्षा ज्ञानार्जन व आत्म–उत्थान के लिए न रहकर व्यवसाय हो गई है, इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। प्राचीन काल की शिक्षा की भाँति इसमें धार्मिक तथा नैतिक तत्वों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा का प्रचार– प्रसार व्यक्ति की योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण में, विश्व–बन्धुत्व की गणना विकसित करने में प्राचीन शिक्षा के उददे्श्यों का प्रयोग किया जा सकता है **एल0एस0 मुदालियर ने कहा था–''**हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए। ईश्वर करे, भावी पीढ़ी उसकी वास्तविक आत्मा को पहचाने और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहे।''

आज हम अपनी पुरानी परम्पराओं आदर्शों और वैभवशाली शिक्षा की विशेषताओं को भूलते जा रहे हैं, हम विदेशों का अनुकरण करने लगे है। वे आदर्श हमारे वास्तविक जीवन से दूर होते है इसलिए हमारा जीवन खोखला हेता जा रहा है। हमारी वर्तमान शिक्षा–प्रणानी गुणात्मकता की तुलना में परिमाणात्मक है। शिक्षा के सभी अंग नीरस व बोझिल होते जा रहे है।। प्राचीन आदर्शों का अनुकरण करके शिक्षा–प्रणाली में समरसता उत्पन्न की जा सकती है छात्रों में नैतिक भावना विकसित कर छात्र–गुरू–शिक्षा के स्वस्थ त्रिकोण को विकसित किया जा सकता है। **डा0 महेशचन्द्र सिंघल कहते हैं–**''हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धान्त के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और जीवन–निर्माण, चरित्र–निर्माण तथा सादा जीवन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उददे्श्यों में स्थान दे सकते हैं।''

आज भले ही वह दिनचर्या अनुकरणीय हो परन्तु उसकी कुछ बातें अवश्य ग्रहण की जा सकती हैं। आज के छात्र हड़ताल करना, एश्वर्यपूर्ण जीवन बिताना और सिनेमा आदि देखना ही पसन्द करते हैं। वर्तमान में प्राचीन काल के छात्रों के उदाहरण को आज के छात्रों को बताकर उनके विचारों में परिवर्तन का प्रयास किया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा क स्वरूप एवं सगंठन (Structure and Organization of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप भारतवर्ष में एक समान नहीं है। विभिन्न राज्यों में इसका ढॉचा विभिन्न बना हुआ हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक सर्वेक्षण में शिक्षा तथा इसके विभिन्न ढॉचों का विवरण इस प्रकार दिया है।

मिडिल स्कूल (Middle Schools)

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इन स्कूल में छठी से आठवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक विद्यालय (Secondary Schools)

इन स्कूलों में मिडिल तथा हाई स्कूल को शिक्षा की व्यवस्था की जाती हैं।

इण्टरमीडिएट विद्यालय (Intermediate College)

इन विद्यालयों में मिडिल, हाई स्कूल तथा इण्टर कक्षाओं की व्यवस्था होती है। ऐसे इण्टर कॉलेज अधिकतर उत्तर प्रदेश में पाये जाते है। इनमें हाई स्कूल के पश्चात् दो वर्ष का पाठ्यक्रम होता है जोकि कक्षा 11 से 12 में विभिन्न पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Higher Secondary Schools)

इन स्कूलों में मिडिल हाई स्कूल तथा हायर सैकेण्डरी कक्षाओं की व्यवस्था होती है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (Industrial Training Institutes)

इनमें कई प्रकार के उद्योगों की शिक्षा दसवी कक्षा प्राप्त करने के पश्चात् दी जाती है, जैसे डिप्लोमा स्टैनोग्राफी बुनने, कातने की शिक्षा, इलैक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, वायरमैन, लेथ मशीन चलाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पालीटेक्निक स्कूल (Polytechnic Schools)

देश के बहुत से राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए पालीटेकनीक स्कूल या कॉलेज हैं, इनमें कई व्यवसायों की शिक्षा जैसे आर्ट तथा क्राफ्ट (Art and Craft) सैक्रोटिरयल प्रैक्टिस (Secretarial Practice) होम क्राफ्ट (Home Craft) डोमैस्टिक सांइस आदि का प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

पालीटेक्निक कॉलेज (Polytechnic College)

इन कॉलिजों में हाई स्कूल पास करने के पश्चात् तीन वर्ष के डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती है, जिसे साधारण ओवरसीअर का डिप्लोमा कहा जाता है।

इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का ढॉचा विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। तकनीकि शिक्षा का ढ़ाँचा कुछ राज्यों में मिलता–जुलता है। शिक्षा के ढ़ाँचे को सार्वभौमिक बनाने के लिए यह विचार किया गया है कि सारे देश में शिक्षा का माध्यमिक स्तर पर एक ही ढ़ाँचा हेना चाहिए। इसी कारण से 1975 में शिक्षा का एक नया ढाँचा तैयार किया गया, जैसे 10+2+3 पद्धति कहते है। बहुत से राज्यों ने इसे अपने राज्यों में लागू कर दिया हैं इस पद्धति के अनुसार सभी बच्चों को दसवी कक्षा तक सभी विषयों का जैसे–विज्ञान,गणित,सामाजिक विष्य इत्यादि का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना है। इस पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा की आयु सीमा तक व्यक्तिगत विभिन्नता (Individual Differences) को कोई महत्व नहीं दिया गया।

+2 स्तर पर इस शिक्षा की दो धाराएं है।

1. **शैक्षिक धारा – Academic Stream**
2. **व्यावसायिक धारा – Vocational Stream**

जो बच्चे शैक्षिक विषयों में विशेष अंक हाई स्कूल में प्राप्त करते है। उन्हे शैक्षिक धारा में प्रवेश मिल जाता है और जो बच्चे व्यवसायिक विषयों में अधिक अंक प्राप्त करते है, उन्हें व्यावसायिक धारा में ही प्रवेश मिल सकता है।

+3 स्तर पर प्रवेश अपने –अपने विशेष क्षेत्र में मिलता है जैसे किसी ने शैक्षिक क्षेत्र में मिल जायेगा। यदि किसी ने +2 स्तर व्यवसायिक क्षेत्र में ही मिल सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा का संगठन (Organization of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा के सगंठन से अभिप्राय है इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, इसका पाठयक्रम

कैसा होना चाहिए, कौन–सी भाषाएँ इस स्तर पर पढ़ाई जानी चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए इत्यादि ?

मुदालियर आयोग, कोठरी आयोग तथा नयी राष्ट्र शिक्षा नीति से इस सम्बन्ध में अपने अलग–अलग विचार दिये है। मुदालियर आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल (Multipurpose School) खोलने की सिफारिश की है जबकि कोठरी आयोग ने पड़ोस के स्कूल (Neighbourhood Schools) खोलने का सुझाव दिया है। नयी शिक्षा नीति ने सारे देश में शिक्षा के सामान्य ढाँचे का सुझाव दिया जो कि 10+2 पद्धति पर आधारित है। माध्यमिक स्तर पर भाषाऐं गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि की शिक्षा के साथ–साथ समुदाय सेवा (Community Service) तथा सामाजिक रूप से लाभकारी उत्पादक कार्य (Socailly Useful Produstive Work) खेल, शरीरिक शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला गृह विज्ञान आदि विषयों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संगठन एक विस्तृत शब्द है, जिसके अन्तर्गत माध्यमिक स्तर का ढाँचा आता है। माध्यमिक शिक्षा का संगठन निजी (Private) तथा सरकारी (Govt) सस्थाएँ करती हैं।

माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ
(Problems of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (Secondary Education Act 1960) ने माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है – वह शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

माध्यमिक शिक्षा व्यक्ति की किशोरावस्था के साथ सम्बन्धित है। इस स्तर पर बच्चे के शरीरिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् और विश्वविद्यालय की शिक्षा के आरम्भ होने तक के समूचे शिक्षा काल को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है।

माध्यमिक शिक्षा की सामान्य समस्याएँ
(General Problems of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की ओर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह न केवल भारत में, परन्तु विश्व के लगभग सभी देशों में सबसे अधिक प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है।

उददे्श्यहीनता की समस्या (Problem of Aimlessness)

माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् प्राप्त करने वाली शिक्षा माना जाता है। जिसका अभी तक कोई विशेष उददे्श्य निर्धारित नहीं किया गया। इसे केवल उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए ही प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त किया जाता है।

यह शिक्षा किसी भी प्रकार से जीवन से सम्बन्धित नहीं है और न ही यह जीवन के लिए शिक्षा देती है।

इस शिक्षा की अवधि 11 से 16 वर्ष तक की आयु सीमा में मानी जाती है। जिसमें बच्चे अधिकतर किशोरावस्था के होते है। जिसका शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक बौद्धिक विकास हो जाता है। और वे अपने तथा दूसरे लिंग (Sex) के सम्बन्ध में जानने के इच्छुक रहते है। इस स्तर पर शिक्षा जीवन से सम्बन्धित नहीं होती, अतः वे अनुशासनहीनता फैलाते है, क्योंकि अध्यापकों द्वारा भी उचित निर्देशन (Guidance) नहीं मिलता।

प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि (Growth of Private School)

माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिगत स्कूलों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जिनमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। अध्यापकों की अधिकतर कमी होती है। और उन्हें पूरा वेतन भी दिया जाता जिससे शिक्षा का स्तर गिर जाता है।

शिक्षण विधियों की समस्या (Problem of Method of Teaching)

किशोरावस्था के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा वे अनुभवी होने चाहिए। इनको पढ़ाने के लिए कौन–सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसकी समस्या अभी तक बनी हुई है।

परीक्षा तथा मूल्यांकन की समस्या (Problem of Examination and Evaluation)

इस स्तर पर परीक्षा का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए यह भी एक समस्या बनायी हुई है।

ढाँचे की समस्या (Problem of Structure)

इस स्तर पर सारे देश में शिक्षा का एक ढाँचा नहीं है, जिसके कारण विभिन्न पाठ्यक्रम का प्रयोग इस स्तर पर किया जाता है, जिससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

पाठ्यक्रम के उपयुक्त न होना (Unsuitable Curriculum)

पाठ्यक्रम न तो जीवन से सम्बन्धित होता है और न ही बच्चों की रूचियों, रूझानों, जीवन अनुभवों के अनुसार होता है। यह नीरस तथा अनुपयुक्त होता है, जिससे विद्यार्थी इसे पढ़ने में न तो रूचि लेते हैं और न ही इसमें सक्रिय भाग लेते है।

अवधि की समस्या (Problem of Duration)

देश के विभिन्न भागों में माध्यमिक शिक्षा की अवधि विभिन्न है, जिससे अवधि की समस्या उत्पन्न हुई है।

अपव्यय तथा अवरोध की समस्या (Problem of Wastage and Stagnation)

इस स्तर पर समाज के संकीर्ण विचारों के कारण लड़कियों को अधिकतर अपव्यय ;जंहमद्ध का शिकार होना पड़ता है और उन्हें स्कूल से उठा लिया जाता है। लड़कों में इस स्तर पर अवरोध लापरवाही के कारण अधिक पाया जाता है।

व्यवसायिक व शैक्षिक निर्देशन की समस्या (Problem of Educational and Vocational Guidance)

इस स्तर पर बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है परन्तु अधिकतर स्कूलों में इस निर्देशन का अभाव है; जिससे विद्यार्थी

मार्ग दर्शन के अभाव में आगे बढ़ते हैं और शैक्षिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विस्तार की समस्या (Problem of Expansion)

जनसंख्या वृद्धि के कारण माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की आवश्यकता दिनों नि बढ़ती जा रही है, परन्तु उत्साह की दरिद्रता के कारण तथा साधनों के अभाव के कारण इतने अधिक स्कूल नहीं खोजे जा सके जिससे माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हो पाया।

प्रबन्ध की समस्या (Problem of Management)

इस स्तर पर कुछ सरकारी स्कूल हैं और कुछ व्यक्तिगत स्कूल (Private Schools) हैं। इनका प्रबन्ध कौन करे। दोहरी नीति होने के कारण इन स्कूलों के प्रबन्ध की समस्या बनी हुई है।

संकीर्णता की समस्या (Problem of Narrowness)

माध्यमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, परन्तु इस शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा और समस्याएँ सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना की जाती है जिससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना सम्भव नहीं है।

कक्षा में अधिक संख्या की समस्या (Problem of Over Crowded Class)

जनसख्या विस्फोट के कारण इस सत्र पर अधिक–से–अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं तथा कक्षा में किसी–न–किसी कारणवश अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, जिससे संख्या को अधिकता के कारण उन्हे उचित शिक्षा नहीं मिल पाती।

समुदाय से सम्बन्धित न होना (Problem of not Related to Community)

माध्यमिक स्तर की शिक्षा न तो समुदाय से, न समुदाय की क्रियाओं और न समुदाय के जीवन से सम्बन्धित होती है। अतः विद्यार्थी इसमें कोई रूचि नहीं ले पाते, क्योंकि वे समुदाय से सम्बन्धित होते हैं, और उसकी गतिविधियों में विशेष रूचि लेते है। अतः समुदाय से शिक्षा के सम्बन्धित न होने के कारण उन्हें यह शिक्षा नीरस लगती है।

माध्यमिक स्तर की समस्याओं के सुलझाने के लिए कोठारी आयोग के सुझाव (Recommendations of Kothari Commission to Solve the Problems)

नामांकन सीमित करना (Restricting Enrolment)

चुने हुए विद्यार्थियों को ही दाखिला दिया जाना चहिए, ताकि सार्वजनिक माँग तथा उपलब्ध सुविधाओं के बीच खाई को समाप्त किया जा सके।

20 वर्षों में नामांकन को नियमित करना (Regulating Enrolment in 20 Year)

1. माध्यमिक विद्यालयों के स्थान की उचित योजना,
2. अच्छे विद्यार्थियों को चुनकर दाखिल करना,
3. पर्याप्त स्तर स्थापित करना–इसके लिए पर्याप्त सुविधाओं के अनुसार नामांकन निश्चित करना।

अंशकालीन शिक्षा (Part-time Education)

योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए लोअर एवं हायर सैकण्डरी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अंशकालिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।

पत्राचार कोर्स (Correspondence Course)

जो व्यक्ति किसी कारणवश अंशकालिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए पत्राचार कोर्स का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

नामांकन नीति की चतुमुर्ख कसौटी (Four-fold Criteria for Enrolment)

नामांकन नीति चतुर्मुख कसौटी पर आधारित होनी चाहिए–

1. सैकण्डरी उच्च शिक्षा के लिए जनता की माँग
2. मानव शक्ति की आवश्यकताएँ
3. प्राकृतिक योग्यता के समूह का पूर्ण विकास
4. वांछित गुणात्मक स्तर पर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने में समाज की योग्यता।

प्रत्येक जिले के लिए योजना और उसका कार्यन्वयन (Planning for Each District and its Implementation)

सभी नयी संस्थाओं में आवश्यक स्तर स्थापित होना चाहिए और विद्यमान संस्थाओं को न्यूनतम स्तर पर अवश्य विकसित करना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalisation of Secondary Education)

इसके लिए विद्यार्थियों को व्यवसायिक कोर्सों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुवधिाएँ दी जानी चाहिए।

लड़कियें के लिए शिक्षा (Education for Girls)

लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाने चाहिए। उन्हें प्रोत्सहित करने के लिए छात्रवृत्तियों भी देनी चाहिए।

नये स्कूलों की योजना और स्थापना की राष्ट्रीय नीति (National Policy for Planning and Location of New Schools)

शिक्षण संस्थाओं के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहिए। व्यावसायिक स्कूल, सम्बन्धित उद्योगों के निकट, स्थापित किये जाने चाहिए।

दाखिले के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थियों को चुनना (Selecting the Best Students for Admission)

लोअर सैकण्डरी स्तर पर आत्म–चुनाव प्रणानी को माध्यमिक शिक्षा और समस्याएँ अपनाना चाहिए और हायर सैकण्डरी स्तर पर बाह्य परीक्षा के परिणामों तथा स्कूल रिकार्ड के आधार पर चुनाव करना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त तो क्या कहें, पर बिल्कुल विपरीत है. अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कई बार अधिक भ्रष्ट दिखता है, हमारी शिक्षा व्यक्ति को विपरीत दिशा में ले जा रही है. इसीलिए आज की शिक्षा प्रणाली तो किसी भी हालत में नहीं चलनी चाहिए. हमारा उद्देश्य भी यही है, देश की शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए. देश की शिक्षा को एक नए विकल्प की आवश्यकता है, और उसके लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं.

जब शिक्षा नीति में बदलाव की बात आएगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक विषय है भाषा का, जबतक देश की भाषा नीति नहीं बदलेगी, तब तक शिक्षा नीति बदलने का अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जीवन की नींव ही शिक्षा है, इसीलिए हमने एक नारा दिया है कि यदि देश को बदलना है तो पहले शिक्षा को बदलना होगा. जब तक देश में शिक्षा नहीं बदलेगी, तब तक देश में वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता. पिछले 150–175 साल में जिस शिक्षा को पढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनका जो मानस बन गया है..उसमें यदि अर्थशास्त्री है तो उसे मार्क्स के सिद्धांत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और चाणक्य की बात करो तो भगवाकरण की बात लगती है. किसी भी व्यक्ति ने 15–20 साल जो पढ़ाई की, तो उसी के आधार पर उसका जीवन बनेगा. शिक्षा ऐसी चीज है, कि छोटी उम्र से बच्चे के मन पर इसका गहरा प्रभाव होता है, बचपन का अधिक प्रभाव होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण मैं कई बार देता हूं कि जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोग भी समझते हुए भी व्यवहार में अनेक बार मत संप्रदाय को भी धर्म ही बोलते हैं, जबकि वे जानते हैं कि धर्म, मत, संप्रदाय अलग–अलग हैं. शिक्षा का मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव होता है, कि बुद्धि नहीं मानती है फिर भी मुंह से वही निकल जाता है. इसलिए जब तक शिक्षा जैसी आधारभूत बातें ठीक नहीं होती, तब तक देश की समस्याएं जो आज दिख रही हैं, उनका समाधान भी बहुत मुश्किल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *माध्यमिक शिक्षाओं समस्याएँ।*
2. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक।*
3. *शिक्षा समाजशास्त्र के मूल तत्व।*
4. *शिक्षा एवं समाज।*
5. *भारतीय शिक्षा का इतिहास।*
6. *उभरते भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका।*
7. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा।*